

पूर्ण बेंच

मेहर सिनगह सी.जे., डी.के. महाजन और बल राज तुली जे.जे.

राम निवास गुप्ता और अन्य, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता

1967 की सिविल रिट संख्या 2975

15 दिसंबर 1969.

पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट (1911 का 111) क्रमांक 47, 661(2) और 62-ए-म्यूनिसिपल कमेटी एक शहर के हिस्से में भूखंडों की नीलामी इस आश्वासन के साथ करती है कि यह चुंगी लगाने से मुक्त होगा-ऐसे सूदखोरी-चाहे का हिस्सा हो अनुबंध-नगरपालिका समिति के साथ किया गया अनुबंध धारा 47 के अनुसार निष्पादित किया गया है-क्या नगर पालिका समिति पर बाध्यकारी है- एस. 62-ए-नगरपालिका समिति से कर लगाने की अपेक्षा करने की सरकार की शक्ति-नगरपालिका समिति द्वारा ऐसा करने में विफलता वह निर्देश-क्या सरकार स्वयं उस कर को लगाने का अधिकार रखती है।

भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 226-संविदात्मक अधिकार-क्या रिट याचिका द्वारा लागू किया जा सकता है।

माना गया कि नगर समिति द्वारा शहर के एक हिस्से में खुली नीलामी द्वारा भूखंडों की बिक्री इस आश्वासन के साथ कि वह हिस्सा चुंगी कर के अधिरोपण से मुक्त होगा, नगरपालिका समिति के बीच भूखंडों की बिक्री के अनुबंध के समान है। और खरीददारों और आश्वासन को बिक्री के अनुबंध के अलावा नगर समिति द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है। पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 61(2) के तहत नगरपालिका समिति को राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन पूरे शहर या उसके किसी भी हिस्से में चुंगी लगाने का अधिकार है।

नगरपालिका समिति को दी गई यह शक्ति उसे संपूर्ण नगरपालिका सीमा या उसके किसी भी हिस्से के भीतर आयातित वस्तुओं पर चुंगी लगाने के लिए अधिकृत करती है। वेतन से छूट. याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया चुंगी का भुगतान अनुबंध से होता है और यह किसी कानून के किसी प्रावधान या किसी कानून के तहत तैयार की गई योजना पर आधारित नहीं है। ऐसा चोर. नगरपालिका समिति द्वारा भूखंडों की बिक्री के ट्रैक्ट, अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित नहीं होने पर, नगरपालिका समिति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और इसके खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते हैं। (पैरा 6 और 7)

माना गया कि अधिनियम की धारा 62-ए के लागू होने के बाद, राज्य सरकार धारा 61 में उल्लिखित किसी भी कर को लगाने के लिए एक समिति की आवश्यकता कर सकती है, जिसमें पहले से नहीं लगाया गया चुंगी शामिल है और यदि नगरपालिका समिति उस निर्देश का पालन नहीं करती है, उस टैक्स को लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार धारा 62-ए का सहारा ले सकती है, भले ही चुंगी पहले से ही नगरपालिका समिति की सीमा के भीतर लगाई गई हो। राज्य सरकार नगरपालिका समिति को कर लगाने का निर्देश दे सकती है और यदि नगरपालिका समिति इसे लगाने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार इसे स्वयं लगा सकती है। (पैरा 8)

माना गया कि संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण उपाय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। (पैरा 6)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 6 नवंबर, 1968 को माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली द्वारा मामले को एक डिवीजन बेंच को भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली की खंडपीठ ने 1 दिसंबर, 1969 को मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया। पूर्ण पीठ में माननीय शामिल थे मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह, माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली ने अंततः 15 दिसंबर, 1969 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ द्वारा पारित संकल्प संख्या 6 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। इसकी विशेष बैठक 21 जुलाई, 1965 को हुई और प्रतिवादी संख्या 1 का आदेश, जैसा कि क्रमशः उनके मेमो संख्या 6106-आईसीआईआई-67/26734, दिनांक 30 अक्टूबर, 1967 द्वारा बताया गया था।

याचिकाकर्ताओं के लिए आर. सच्चर, सत्य प्रकाश जैन और जी. सी. गर्ग, वकील के साथ।

डी. एस. तेवतिया, महाधिवक्ता (हरियाणा) के साथ बी. एस. गुप्ता और सी. बी. कौशिक, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए अधिवक्ता और यू. डी. गौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

पूर्ण पीठ का निर्णय

तुली, जे. ये दो रिट याचिकाएँ (1967 की सिविल रिट 2975, राम निवास गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, और 1968 की सिविल रिट 444, मेसर्स जीत राम शिव कुमार और अन्य: बनाम हरियाणा राज्य और दूसरे) पहली बार में मेरे सामने सुनवाई के लिए आए और मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय के लिए उन्हें एक डिवीजन बेंच के पास भेज दिया कि म्यूनिसिपल कमेटी, सोनीपत बनाम धरम चंद और लाहौर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का एक फैसला था। अन्य (1)¹, जिसकी सत्यता पर संदेह किया गया था। मेरे संदर्भ आदेश के अनुसरण में, इन याचिकाओं को 1 दिसंबर 1969 को मेरे भगवान मुख्य न्यायाधीश और मेरे द्वारा गठित एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था, और हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक पूर्ण पीठ को संदर्भित किया था कि लाहौर का फैसला एक डिवीजन बेंच का फैसला है। इस प्रकार ये रिट याचिकाएँ निर्णय हेतु इस पूर्ण पीठ के समक्ष आई हैं। फैसले से दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा हो जाएगा।

(2) तथ्य यह है कि नगर पालिका, बहादुरगढ़। 1916 में फतेह मंडी के नाम से जानी जाने वाली एक मंडी स्थापित करने का निर्णय लिया गया 20 नवंबर, 1916 के संकल्प संख्या 8 द्वारा नीलामी की शर्तों को तय किया गया। बिक्री की शर्तों में से एक, अर्थात् संख्या 14, यह थी कि मंडी चुंगी कर लगाने से मुक्त होगी, लेकिन इसके मालिक मंडी में भूखंडों को गृह-कर का भुगतान करना होगा जो मंडी के खर्चों को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है। 20 मई, 1917 को आयोजित एक विशेष बैठक में, नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ ने प्रस्ताव संख्या 4 पारित किया, जिसमें प्रावधान किया गया कि फतेह मंडी में भूखंडों की बिक्री की शर्तों की अवधि संख्या 14 में संशोधन किया जाए ताकि यह पढ़ा जा सके कि मंडी बनी रहेगी। चुंगी कर के भुगतान से सदैव के लिए प्रतिरक्षित। आयुक्त, अंबाला डिवीजन ने इस शब्द पर आपत्ति जताई और अपने पत्र संख्या 2454, दिनांक 26 जून, 1917 द्वारा, उपायुक्त, रोहतक को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष, नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ को एक प्रति के साथ, संकल्प संख्या के प्रति अपनी अस्वीकृति की सूचना दी। 4, दिनांक 20 मई, 1917। नगरपालिका समिति ने अपने संकल्प संख्या 6, दिनांक 30 अगस्त, 1917 द्वारा, आयुक्त, अंबाला डिवीजन से बिक्री की घोषणा में शर्त संख्या 14 की पुष्टि करने का अनुरोध किया। अपने पत्र क्रमांक 3627/एम-40-एलएफ, दिनांक 20 सितंबर, 1917 को

¹ A.I.R. 1935 Lah. 632

आयुक्त ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति वापस ले ली, लेकिन पत्र में कहा गया कि "जैसे ही बाजार स्थापित होगा, यह आवश्यक होगा यह विचार करने के लिए कि नगर निगम के खर्चों की बाजार हिस्सेदारी को कवर करने के लिए किस प्रकार का कराधान सर्वोत्तम है"। संकल्प संख्या 1, दिनांक 10 मार्च, 1919 द्वारा, नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ ने रुपये की दर से गृह कर लगाया। 3/14 मण्डी के दुकानदारों को एक व्यय पूरा करने के लिए वार्षिक मूल्य का 6 प्रतिशत -

लगभग रु. का ट्यूर. उक्त बाजार के लिए प्रति वर्ष 800 रु. (3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि बहादुरगढ़ नगर पालिका की सीमा के अन्य हिस्सों में चुंगी लगाई जा रही थी लेकिन फतेह मंडी को चुंगी सीमा से बाहर रखा गया था। अधिसूचना संख्या 9697-सीसी53/63830, दिनांक 4 सितंबर, 1958 द्वारा, नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ की चुंगी सीमा को बढ़ा दिया गया और नगरपालिका सीमा के साथ कोर्टमिनस कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फतेह मंडी को चुंगी सीमा में शामिल कर लिया गया। परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, ने नगरपालिका समिति के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान नगरपालिका समिति द्वारा फतेह मंडी में आयातित माल को चुंगी के भुगतान से छूट देने पर आपत्ति जताई और जोर दिया कि चुंगी लगाई जानी चाहिए उस मण्डी में आयातित माल पर। म्यूनिसिपल कमेटी ने पूरे मामले पर पुनर्विचार किया और 2 मार्च, 1954 के संकल्प संख्या 1 द्वारा निर्णय लिया कि फतेह मंडी, बहादुरगढ़, बिक्री से संबंधित बिक्री के पूर्व-ग्रहण की शर्तों के अनुसार चुंगी के भुगतान से मुक्त रहेगी। उक्त मंडी में भूखंड। यह उस तिथि को आयोजित समिति की एक विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 70(2) के तहत पुष्टि के लिए पंजाब राज्य को भेजा गया था। पंजाब सरकार ने 4 मई, 1954 को एक ज्ञापन द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि की।

(4) म्यूनिसिपल कमेटी, बहादुरगढ़ ने 8 मई 1954 को हुई बैठक में इस मामले पर पुनर्विचार किया और उस तारीख के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा फतेह मंडी में आयातित माल पर चुंगी लगाने का निर्णय लिया लेकिन पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अधिनियम की धारा 236 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और उस आदेश की एक प्रति अध्यक्ष, नगर समिति को पृष्ठांकन संख्या 2768-सीसी-54/11442, दिनांक 17 मई, 1954 द्वारा सूचित की गई थी। परीक्षक, स्थानीय निधि के बाद से अकाउंट्स, पंजाब, फतेह मंडी, बहादुरगढ़ में आयातित माल पर चुंगी लगाने पर जोर दे रहा था। मंडी के प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वशासन विभाग, पंजाब सरकार के सचिव के साथ इस मामले पर चर्चा की, जिन्होंने अपने ज्ञापन द्वारा। संख्या 3159-सी-58/26258, दिनांक 9 अप्रैल, 1956 ने नगरपालिका समिति के अध्यक्ष को सूचित किया कि सरकार की कार्रवाई 2 मार्च 1954 के संकल्प संख्या 1 की पुष्टि

करती है। फतेह मंडी में आयातित माल को कर से छूट दी गई है। अधिनियम की धारा 70(2)(सी) के तहत चुंगी बिल्कुल ठीक थी और नियमों के तहत इस आशय की कोई अलग अधिसूचना आवश्यक नहीं थी और परीक्षक। स्थानीय निधि खाते, पहले से ही सरकार के निर्णय से प्रसन्न थे। नतीजा यह हुआ कि फतेह मंडी के दुकानदारों पर कोई चुंगी नहीं लगाई गई।

(5) 21 जुलाई 1965 को आयोजित नगर समिति की एक विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार से 2 मार्च के संकल्प संख्या 1 के अनुमोदन को रद्द करने का अनुरोध किया जाए। 1954 और वह चुंगी फतेह मंडी के दुकानदारों से वसूल की जाए। इस प्रस्ताव को हरवाना राज्य और बीवी मेमो माना गया। संख्या 6406-1-सी-द्वितीय/26734, दिनांक 30 अक्टूबर 1967, सरकार ने 21 जुलाई 1965 को समिति द्वारा पारित संकल्प संख्या 6 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस ज्ञापन के प्राप्त होने पर, नगरपालिका समिति ने शुल्क लेना शुरू कर दिया फतेह मंडी, बहादुरगढ़ में आयातित माल पर कर लगाया गया, जिससे याचिकाकर्ताओं को नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ द्वारा पारित 21 जुलाई, 1965 के संकल्प संख्या 6 को रद्द करने और इसके अनुमोदन के लिए इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिकाकर्ता दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर, 1967 को सूचित किया।

(6) रिट याचिकाओं के प्रतिवादी हरियाणा राज्य और नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ हैं, दोनों ने रिट याचिकाओं पर रिटर्न दाखिल किया है और मुख्य मुद्दा यह है कि नगरपालिका समिति और सरकार के पास छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। फतेह मंडी के दुकानदारों को हमेशा के लिए चुंगी शुल्क से छूट। नगरपालिका समिति ने भी प्रारंभिक आपत्ति ली थी कि याचिकाकर्ताओं ने उनके किसी वैधानिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया है और इसलिए, रिट बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

• हम नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में तथ्य पाते हैं। याचिकाकर्ता नीलामी की शर्तों के आधार पर चुंगी के भुगतान से छूट का दावा कर रहे हैं, जिसे नगरपालिका समिति ने संकल्प संख्या 8, दिनांक 20 नवंबर, 1916 द्वारा अनुमोदित किया था, जैसा कि संकल्प संख्या 4, दिनांक मई, 20 द्वारा संशोधित किया गया था।, 1917, और आयुक्त, अम्बाला डिवीजन से सहमत हुए। उनका कहना है कि खरीददारों ने बिक्री की शर्त संख्या 14 को स्वीकार कर लिया और उस पर विश्वास करते हुए भूखंड खरीदे, जिसके परिणामस्वरूप नगर समिति और भूखंडों के खरीददारों के बीच एक अनुबंध हुआ और नगर समिति को वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उस पर. उत्तर में प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि नगरपालिका समिति और

याचिकाकर्ताओं के बीच कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि अधिनियम की धारा 47 के अनुसार कोई अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया था और इसलिए, धारा 47 के आधार पर (3). नगरपालिका समिति याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी अनुबंध से बंधी नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 46 के तहत लेनदेन को नगरपालिका समिति द्वारा एक बैठक में अनुमोदित किया जाना आवश्यक था जो कभी नहीं किया गया और इसलिए, याचिकाकर्ताओं और नगरपालिका समिति के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ। लिखित बयानों में अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है, लेकिन अधिनियम की धारा 47 के संबंध में दलील जरूर ली गई है। लिखित बयानों के लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई थी और रिट याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि भूखंडों की खरीद के संबंध में अनुबंध धारा 47 के अनुसार निष्पादित नहीं किए गए थे। अधिनियम, शून्य थे और नगरपालिका समिति पर बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि नगरपालिका समिति को भूखंडों की बिक्री के समय खरीदारों को दिए गए आश्वासन से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कोई चुंगी नहीं लगाई जाएगी। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक भरोसा जताया है भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स एंग्लो अफगान एजेंसियां, आदि (2)² में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के फैसले पर। । यह उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया: -

“यह कुछ हद तक कमजोर रूप से आग्रह किया गया था कि यदि सरकार को अपने इरादे के बारे में उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व से बाध्य माना जाता है, जब निर्यातकों ने उस तरीके से कार्य किया है जिस तरह से उन्हें कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो सरकार को एक संविदात्मक दायित्व से बाध्य माना जाएगा, भले ही कोई न हो संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा अपेक्षित तरीके से औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया गया था, और निर्यातक अनुबंध के उल्लंघन के लिए उस प्रावधान के विपरीत नुकसान का दावा करने का हकदार होगा, भले ही कोई औपचारिक लिखित अनुबंध प्रदान किए गए तरीके से निष्पादित नहीं किया गया हो। उस अनुच्छेद द्वारा। लेकिन उत्तरदाता किसी भी संविदात्मक अधिकार को लागू करने की मांग नहीं कर रहे हैं: वे उस दायित्व के अनुपालन को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो योजना की शर्तों के अनुसार कपड़ा आयुक्त पर लगाया गया है, और हमारा विचार है कि भले ही योजना चरित्र में कार्यकारी है, प्रतिवादी, जो योजना की शर्तों को पूरा करने में विफलता के कारण व्यथित थे, न्यायालय का सहारा लेने और दावा करने के हकदार थे कि कपड़ा आयुक्त पर दायित्व लगाया गया था योजना को क्रियान्वित करने का आदेश दिया जाए।”

² A.I.R. 1968 S.C. 718.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस मामले में याचिकाकर्ता किसी संविदात्मक अधिकार की पूर्ति का दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि कपड़ा आयुक्त से निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कह रहे थे, जिसे आयात और निर्यात (नियंत्रण) के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। अधिनियम, 1947 का 18। उनके आधिपत्य ने निश्चित रूप से कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी संविदात्मक अधिकार को लागू नहीं कर रहे थे जो उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करता है कि संविदात्मक अधिकारों को अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान. फतेह मंडी में भूखंडों की बिक्री के लिए नीलामी की शर्तों को निर्यात प्रोत्साहन योजना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और इसे एक कार्यकारी अधिनियम नहीं कहा जा सकता है जिसके तहत कपड़ा आयुक्त उक्त योजना के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। नीलामी की शर्तों में नगरपालिका समिति और के बीच भूखंडों की बिक्री के अनुबंध की शर्तें भी शामिल थीं याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों के हित में और उन्हें नगरपालिका समिति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के रूप में नहीं कहा जा सकता है। बिक्री की शर्तों की अवधि 14, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करते हैं और जिसे 20 नवंबर, 1916 और 20 मई, 1917 को पारित प्रस्तावों द्वारा नगरपालिका समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, भूखंडों के हस्तांतरण की शर्तों में से एक बन जाती यदि ऐसा कोई भी संप्रेषण नगरपालिका समिति द्वारा क्रेताओं के पक्ष में निष्पादित किया गया था। अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत नगरपालिका समिति को राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन पूरे शहर या उसके किसी भी हिस्से में चुंगी लगाने का अधिकार है। नगरपालिका समिति को दी गई यह शक्ति उसे संपूर्ण नगरपालिका सीमा या उसके किसी भी हिस्से के भीतर आयातित माल पर चुंगी लगाने के लिए अधिकृत करती है और एकमात्र आधार जिस पर याचिकाकर्ता चुंगी के भुगतान से छूट चाहते हैं वह नीलामी की शर्त संख्या 14 है। . लेकिन उस शर्त के लिए उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे नगरपालिका समिति को चुंगी देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए ऑक्ट्रैड के भुगतान से छूट का यह अधिकार सीधे तौर पर नगरपालिका समिति से फतेह मंडी में भूखंडों की खरीद के संबंध में अनुबंध से आता है और यह किसी कानून के प्रावधानों या इसके तहत तैयार की गई योजना पर आधारित नहीं है। एक कानून. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपातिक निर्णय इन मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण उपाय का सहारा संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह केवल याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के कानूनी अधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न शिकायत के निवारण के लिए है। याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे किसी कानूनी अधिकार की वकालत नहीं की गई है। उन्होंने चुंगी के भुगतान से छूट का दावा करने का अपना अधिकार केवल ऊपर बताई गई नीलामी की शर्तों की अवधि 14 पर आधारित किया है। इसे लेखराज सथरामदास लालवानी

बनाम एन.एम. शाह, उप संरक्षक-सह-प्रबंध अधिकारी, बॉम्बे और अन्य (3)³ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा निम्नानुसार माना गया है: -

"लेकिन इस धारणा पर भी कि अपीलकर्ता के प्रबंधन को समाप्त करने वाला उप संरक्षक का आदेश अवैध है, अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की प्रकृति में रिट देने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का हकदार नहीं है। कारण यह है कि परमादेश की रिट केवल उसी मामले में दी जा सकती है जहां संबंधित अधिकारी पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया हो और उसकी ओर से कोई विफलता हो अधिकारी उस वैधानिक दायित्व का निर्वहन करें। रिट का मुख्य कार्य कानून द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए बाध्य करना और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर सार्वजनिक कार्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना है।

मौजूदा मामलों में उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन की शिकायत नहीं की गई है और न ही यह बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को किस वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने का आदेश दिया जा सकता है।

(7) सत्य प्रकाश और अन्य बनाम आयुक्त, भूमि सुधार और जागीर, एम.बी., और अन्य (4)⁴ मामले में मध्य भारत उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक ऐसे मामले का निपटारा किया जिसमें अनुबंध निष्पादित नहीं किए गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 (1) द्वारा आवश्यक प्रपत्र और इसलिए, सरकार पर बाध्यकारी नहीं थे और इसके खिलाफ लागू करने योग्य नहीं थे। इन तथ्यों पर, विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नानुसार निर्णय दिया: -

“याचिकाकर्ता, इसलिए, यह दावा नहीं कर सकते कि उन अनुबंधों के तहत उनके पास वन क्षेत्रों में काम करने और निर्मित चारकोल, कत्था और काटी गई सामग्री पर कानूनी और लागू करने योग्य अधिकार हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि डी.एफ.ओ. को इसमें प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया गया था सरकार की ओर से अनुबंध और यदि उसने वन क्षेत्रों के काम के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ कोई समझौता किया है, तो याचिकाकर्ता मुआवजे की राहत के हकदार हो सकते हैं।

³ A.I.R. 1966 S.C. 334.

⁴ AIR 1955 M.B 188

लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है. यहां, याचिकाकर्ता अनुबंधों के तहत वन क्षेत्रों और निर्मित सामग्री पर काम करने के अधिकार को लागू करने का दावा करते हैं जो अप्रवर्तनीय हैं। अनुबंध अप्रवर्तनीय होने के कारण, उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसे अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी निर्देश या रिट द्वारा लागू किया जा सके।“

उस मामले के तथ्य मौजूदा दो मामलों के तथ्यों के समान हैं क्योंकि भूखंडों की बिक्री के अनुबंध, अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित नहीं होने के कारण, नगरपालिका समिति पर बाध्यकारी नहीं हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती. उन शून्य अनुबंधों से उत्पन्न होने वाली कोई भी राहत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके दावा किया जा सकता है। इन याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता नगरपालिका समिति को बिक्री के अनुबंध का उल्लंघन करने से रोकने की मांग कर रहे हैं, जिसकी एक शर्त यह थी कि कोई चुंगी नहीं लगाई जाएगी। हमारी राय में ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है

(8) उत्तरदाताओं की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि 1953 के पंजाब अधिनियम 48 द्वारा, अधिनियम में धारा 62-ए शामिल की गई थी जो इस प्रकार है: -

“62-ए। कराधान में सरकार की शक्ति। (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, एक समिति से धारा 61 में उल्लिखित कोई भी कर लगाने की अपेक्षा कर सकती है, जो पहले से ही ऐसी दर पर और उसके भीतर नहीं लगाया गया है ऐसी अवधि जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है और समिति उसके अनुसार कार्य करेगी।

(2) राज्य सरकार पहले से लगाए गए किसी भी कर की दर को संशोधित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता कर सकती है और उसके बाद समिति राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अवधि के भीतर आवश्यकतानुसार कर को संशोधित करेगी।

(3) यदि समिति उप-धारा (1) या (2) के तहत पारित किसी भी आदेश को पूरा करने में विफल रहती है, तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित एक उपयुक्त आदेश द्वारा, कर लगा सकती है या

संशोधित कर सकती है। इस प्रकार पारित आदेश ऐसे संचालित होगा जैसे कि यह समिति द्वारा विधिवत पारित एक प्रस्ताव हो और जैसे कि प्रस्ताव धारा 62 में निहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।“

इस धारा के अधिनियमित होने के बाद से, राज्य सरकार धारा 61 में उल्लिखित किसी भी कर को लगाने के लिए एक समिति की आवश्यकता कर सकती है, जिसमें चुंगी भी शामिल है, जो पहले से नहीं लगाई गई है और यदि नगरपालिका समिति उस निर्देश का पालन नहीं करती है, तो राज्य सरकार के पास यह अधिकार है। वह टैक्स लगाओ। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क यह है कि धारा 62-ए का सहारा राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि चुंगी पहले से ही नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ की सीमा के भीतर लगाई गई है। हालाँकि, यह तर्क बलहीन है क्योंकि फतेह मंडी में राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर, 1967 को संकल्प संख्या 6, दिनांक 21 जुलाई, 1965 को मंजूरी देने से पहले चुंगी नहीं लगाई गई थी और इसलिए, उस पर राज्य सरकार नगरपालिका समिति, बहादुरगढ़ को वह कर लगाने का निर्देश दे सकती थी और यदि नगरपालिका समिति ऐसा कर लगाने में विफल रहती, तो राज्य सरकार इसे स्वयं लगा सकती थी। इसका परिणाम यह है कि यदि रिट याचिकाएँ स्वीकार भी कर ली जाती हैं, तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 62-ए के तहत एक उचित अधिसूचना जारी करके उसके प्रभाव को समाप्त कर सकती है। यह कहना स्वयंसिद्ध है कि यह न्यायालय निरर्थक रिट या रिट जारी नहीं करता है जिसे उत्तरदाताओं द्वारा एक कानून के तहत एक अधिसूचना द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(9) ये याचिकाएँ ऊपर निर्धारित दो आधारों पर खारिज की जा सकती हैं और इन याचिकाओं में आग्रह किए गए अन्य बिंदुओं पर विद्वान वकील के तर्कों से निपटना आवश्यक नहीं है। ऐसा पहला बिंदु यह है कि उत्तरदाताओं को नीलामी नोटिस की अवधि 14 द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के विपरीत चुंगी लगाने से इक्विटी में रोक दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दादोबा जनार्दन बनाम बॉम्बे के कलेक्टर (5)⁵, बॉम्बे शहर के नगर निगम बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव (6)⁶, बॉम्बे के कलेक्टर पर भरोसा जताया है। बनाम बॉम्बे शहर का नगर निगम और अन्य (7)⁷ और भारत संघ और अन्य बनाम मेसर्स एंग्लो-अफगान एजेंसियां, आदि, (सुप्रा), (2)। पिछले उल्लिखित मामले में उनके आधिपत्य के फैसले के पैरा 19 पर विशेष जोर दिया गया है जिसमें यह देखा गया था: -

⁵ ILR 25Bom 714

⁶ ILR 29 Bom 580

⁷ AIR 1951 SC 469

"हमारा मानना है कि उत्तरदाताओं का दावा उचित रूप से उस इक्विटी पर आधारित है जो निर्यात संवर्धन योजना में भारत संघ की ओर से किए गए प्रतिनिधित्व और उस पर कार्रवाई करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उनके पक्ष में उत्पन्न होती है। इस विश्वास के तहत प्रतिनिधित्व कि सरकार उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को पूरा करेगी। इस मामले में साबित तथ्यों पर, निर्यातकों द्वारा उनके पूर्वाग्रह के तहत किए गए कृत्यों से उत्पन्न इक्विटी से सरकार को छूट देने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई आधार नहीं सुझाया गया है। प्रतिनिधित्व पर भरोसा करते हुए।"

रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के अभाव में समानता की इस दलील को इन याचिकाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता फतेह मंडी में भूखंडों के मूल खरीदार नहीं हैं। वे या तो भूखंडों के मूल खरीददारों के वंशज हैं, या उनसे हस्तांतरित हैं। माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्तियों को क्या अधिकार दिए गए थे, यह निर्धारित करने के लिए नगरपालिका समिति द्वारा मूल खरीददारों के पक्ष में कोई बिक्री-विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि यदि चुंगी के भुगतान से छूट के बारे में शर्त 14 नहीं होती तो मूल खरीददारों ने प्लॉट नहीं खरीदे होते या उन्होंने जो कीमत चुकाई होती वह नहीं चुकाई होती। यह याद रखना होगा कि मंडी में दुकानों की जगहें नीलाम की गई थीं और निजी बातचीत या निविदाएं आमंत्रित करके नहीं दी गई थीं। 20 नवंबर 1916 को पारित प्रस्ताव संख्या 8 के 20 मई 1917 को संशोधित होने से पहले दुकानें नीलाम हो चुकी थीं। उक्त संशोधन में कहा गया कि मंडी हमेशा के लिए चुंगी के भुगतान से मुक्त रहेगी। 1916 में जब भूखंडों की नीलामी की गई थी तब मूल खरीदारों को यह प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। नीलामी-बिक्री की शर्तों में से एक के बाद के संशोधन को नगर समिति को चुंगी लगाने से रोकने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, गवाही पर रोक के अलावा एस्टॉपेल का कोई संचालन या प्रभावकारिता नहीं है। इसका एकमात्र कार्य या तो किसी ऐसे मामले के रास्ते में बाधा डालना है जो अन्यथा सफल हो सकता है, या किसी ऐसे मामले के रास्ते से बाधा को हटाना है जो अन्यथा विफल हो सकता है। इसका कोई अन्य कार्य नहीं है। सशक्त रूप से यह अपने आप में कार्य का कारण नहीं है; न ही यह किसी का निर्माण करता है, हालांकि मुकदमेबाजी के दौरान साक्ष्य के किसी अन्य नियम के रूप में इसके आवेदन से एक या अन्य पक्षों द्वारा किए गए मामले की पूर्ण या आंशिक स्थापना या विघटन हो सकता है। एस्टॉपेल केवल मुकदमे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है; यह अधिकार को समाप्त नहीं करता है। याचिकाकर्ता उनसे चुंगी की वसूली के लिए कार्यवाही में रोक लगाने का अनुरोध करने में सक्षम हो सकते हैं, यदि कोई नगरपालिका समिति द्वारा लाया जाता है, लेकिन वे अदालत में नहीं आ सकते हैं और कह सकते हैं कि नगरपालिका समिति को किसी भी चुंगी को लगाने या एकत्र करने से रोका जाना चाहिए। बिक्री की शर्तों की अवधि 14 पर उनके

अधिकार के आधार पर उनसे। हालाँकि, पर्याप्त सामग्री के अभाव में इस मामले को इन रिट याचिकाओं में अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक उचित मामले में और एक उचित मंच के समक्ष यह निर्धारित करना होगा कि क्या मूल खरीददारों में से हस्तांतरित व्यक्ति एस्टॉपेल या इक्विटी की दलील ले सकता है और किस हद तक। उस उद्देश्य के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि मूल खरीदारों ने किस प्रतिनिधित्व या शर्तों पर भूखंड खरीदे हैं और याचिकाकर्ताओं ने, जो मूल खरीदारों से हस्तांतरित हैं, किन शर्तों पर दुकानें खरीदी हैं। उस प्रयोजन के लिए उनके पक्ष में विक्रय-पत्रों का अवलोकन आवश्यक होगा। इन याचिकाओं द्वारा कोई बिक्री पत्र प्रस्तुत या संदर्भित नहीं किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के समक्ष यह दावा उन निर्यातकों द्वारा किया गया था जिन्होंने निर्यात प्रोत्साहन योजना के विश्वास पर काम किया था जिसे केंद्र सरकार ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और कपड़ा आयुक्त के प्रावधानों के तहत तैयार किया था। उस योजना के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। कहा गया था कि इक्विटी इस आधार पर निर्यातकों के पक्ष में उत्पन्न हुई थी कि योजना के प्रावधानों के विश्वास पर, जो कि केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के बराबर था, उन्होंने निर्यात करके अपने पूर्वाग्रह के तहत काम किया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे शत-प्रतिशत आयात कोटा के हकदार थे और कपड़ा आयुक्त की इच्छा से आयात कोटा कम नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, इन दोनों मामलों के तथ्य अलग-अलग हैं और उचित सामग्री के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा कि क्या उस मामले के अनुपात निर्णय को इन मामलों के तथ्यों पर लागू किया जा सकता है।

(10) उत्तरदाताओं की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि 1916 में फतेह मंडी में नीलामी द्वारा भूखंडों की बिक्री से संबंधित लेनदेन पार्टियों के बीच अनुबंध थे और उक्त अनुबंधों को लिखित रूप में कम नहीं किया गया था और न ही निष्पादित किया गया था। अधिनियम की धारा 47 में निर्धारित औपचारिकताओं के कारण, याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों को कोई भी लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिलता है और किसी को भी नगर पालिका के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार की मंजूरी के साथ अधिनियम की धारा 21(2) के तहत कर लगाने की शक्ति विधायी शक्ति का प्रयोग है और ऐसी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ कोई रोक या इक्विटी का अनुरोध नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी 1 की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि कर के भुगतान से छूट या छूट देने की शक्ति भी एक विधायी शक्ति है और एक बार दी गई छूट हमेशा रद्द की जा सकती है। इस तर्क पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तर यह है कि उनके पूर्ववर्तियों को दी गई चुंगी के भुगतान से छूट या प्रतिरक्षा विचार द्वारा समर्थित थी और इसलिए, नगरपालिका समिति उस छूट या प्रतिरक्षा को वापस नहीं ले सकती थी। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि अधिनियम की धारा 70 उप-धारा (2) के अनुसार कोई छूट कभी नहीं दी गई क्योंकि

राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी जो अनिवार्य थी और धारा 70 उप-धारा से अलग थी। (2) अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगरपालिका समिति को कर के भुगतान से हमेशा के लिए छूट देने का अधिकार देता हो और यहां तक कि उस उपधारा के तहत भी छूट दी गई हो। हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता. संक्षेप में तर्क यह है कि प्रतिरक्षाकर के भुगतान से हमेशा के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती और अवधि संख्या 14 नीलामी द्वारा बिक्री नगरपालिका समिति की शक्तियों के दायरे से बाहर थी और इसे लागू नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि नगरपालिका समिति के पास अधिनियम की धारा 188 (जी) के तहत चुंगी एकत्र करने के उद्देश्य से सीमा तय करने की शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए नगरपालिका समिति ने फतेह मंडी को बाहर कर ऐसी सीमाएं तय कीं। तथा नगरपालिका समिति को नीलामी-बिक्री की अवधि संख्या 14 के कारण फतेह मण्डी को चुंगी सीमा से बाहर रखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इन सभी मामलों में कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं और, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, रिकॉर्ड पर सामग्री की कमी के कारण इन रिट याचिकाओं में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा अपने-अपने तर्कों के समर्थन में कई निर्णय हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, लेकिन हमें उन्हें संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इन दलीलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं और पहले दो आधारों पर इन याचिकाओं को खारिज करना पसंद करते हैं। ऊपर उल्लिखित.

(11) ऊपर दिए गए कारणों से, इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन रिट याचिकाओं में पूछे गए प्रश्नों की कठिन प्रकृति के कारण लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के।

मेहर सिंह, सी.पी.-में सहमत हूं। डी.के. महाजन, जे.-में भी ऐसा ही करता हूँ।

आर.एन.एम.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा